Malpractices in Letters of Intent for Setting up Industries in Backward Areas

2377. SHRIMATI KRISHNA KAUL: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have seen press report to the effect that people do not set up an industry in backward areas even though they profess to do so and use the letters of intent for blocking the capacity; and

(b) if so, the steps the Central Government have taken to check such malpractices in regard to letters of intent issued by them?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) and (b) There have been press reports to the effect that letters of intent granted for setting up industrial capacities in backward areas are not implemented and that there has been blocking of capacity. Implementation of letters of intent are monitored by the administrative Ministries and validity of the letters of intent are extended by them only after satisfying that the parties have taken appropriate steps towards implementation of the letters of intent. It has also been prescribed that generally letters of intent can be extended only upto a period of five years after which the letters of intent will be treated as lapsed.

सरकारी क्षेत्र में भारी उद्योग

2378. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :**
श्री राम चन्द्र विकल :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी क्षेत्र में कितने भारी उद्योग चलाये जा रहे हैं तथा उनमें से प्रत्येक में कितनी पूंजी का निवेश किया गया है, उनकी अलग-अलग वार्षिक खपत कितनी है तथा उनकी इस मांग को किस तरह से पूरा किया जाता है ; और

(ख) क्या यह सच है कि जापान में भारी उद्योगों की 90 प्रतिशत आवश्यकता को मध्यम और लघु उद्योगों द्वारा पूरा किया जाता है तथा मध्यम दर्जे के उद्योग बदले में अपनी मांग को छोटे और लघु उद्योगों के द्वारा पूरा करते हैं जिसके फलस्वरूप उद्योग गांव के स्तर तक फैल गये हैं और इस तरह से गांव को शहरों में बदल दिया गया है, यदि हां, तो क्या भारत सरकार की कोई ऐसी योजना है जिसके द्वारा इस प्रकार के मध्यम दर्जे, लघु उद्योग और भारी उद्योगों के सहायक उद्योगों के आधार पर ऐसे स्थानों पर उद्योगों को स्थापित किया जा सके, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार इस संबंध में भविष्य में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) 31-3-1986 को 128 भारी उद्योगों में उनकी सकल परिसम्पत्ति के रूप में 51,080.23 करोड़ रुपये का पूंजी-निवेश किया गया है। उनकी अलग-अलग वार्षिक खपत और ऐसी खपत को पूरा करने की पद्धति का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ख) जापान के भारी उद्योगों की मध्यम और लघु उद्योगों द्वारा पूरी की जा रही मांग की सही प्रतिशतता ज्ञात नहीं है। सरकार ने सरकारी क्षेत्र के नाभिकीय क्षेत्र के आस-पास आर्थिक दृष्टि से सक्षम सहायक उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न सदुपाय किये हैं, जिनके परिणामस्वरूप 31-3-1986 तक 1800 एकक स्थापित किये जा चुके हैं।

Consignment Agents of IPCL

2379. SHRI ALADI ARUNA *alias* V. ARUNACHALAM: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) what are the norms laid down by the Indian Petro-chemicals Corporation

Limited for appointing their consignment agents for distribution of their products along with names of the products;

(b) the names and addresses of the appointed consignment agents at different places, Statewise, area allotted, period, alongwith the terms of appointment rates of commission and when their terms are to expire individually; and

(c) the names of the places and area under their jurisdiction which are lying unrepresented and since when?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETRO-CHEMICALS IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI R. K. JAICHANDRA SINGH): (a) The norms laid down by M/s. Indian Petrochemicals Corporation Limited (IPCL) for selection of the consignment stockists are—good financial standing, adequate experience in selling industrial/consumer products, adequate warehousing facilities, office infrastructure and communication facilities. The products sold through consignment stockists are low density polyethylene, polypropylene, polypropylene copolymer, poly vinyl chloride, linear low density polyethylene and hydrocarbon resin.

(b) A statement is laid on the Table of the House. [*See* Appendix CXLIV, Annexure No. 104.]

(c) IPCL is able to service the potential areas with their existing distribution network.

डबल बाटल कनैक्शनों की सुविधा

2380. **श्री पुनील कुमार पट्टनायक :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद सदस्यों और अतिविशिष्ट व्यक्तियों द्वारा अनुशंसित खाना पकाने की गैस के कनैक्शनों पर वितरकों द्वारा ऐसे उपभोक्ताओं को जो, डबल बाटल कनैक्शन लेना चाहते हैं, डबल बाटल कनैक्शन जारी नहीं किए जाने हैं जिसके परिणाम स्वरूप उपभोक्ताओं को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों में डबल बाटल कनैक्शन न दिये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार इस संबंध में तेल कम्पनियों को आवश्यक आदेश जारी करने का विचार रखती है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) प्राथमिकता के आधार पर दिये गये एल पी जी कनैक्शनों के मामले में दो सिलिंडर वाले कनैक्शन अनुरोध किये जाने पर दिये जाते हैं।

Seventh Plan Power Targets

2381. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item in the "Hindustan Times" of 5th October, 1987 captioned "Power scenario is not too bright" to the effect that the Governmen is not in a position to achieve the target of 280 billion units during the Seventh plan period;

(b) whether Government have focussed their attention on the use of gas based turbines for power generation since natural gas is available in the country; and

(c) what other steps Government have taken to achieve the Seventh Plan targets in power generation?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF POWER IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI): (a) Yes, Sir.

(b) Proposals for setting up of gas turbine plants are examined keeping in view the availability of gas/fuel, the power requirements of the region and other relevant techno-economic considerations.